''पायलट राष्ट्रीय नेता, स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस हर जगह भेजती है, केवल एमएलए के तौर पर उन्हें नहीं देखा जा सकता''

जयपुर (का.प्र.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से अब तक सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिलने के सवाल पर पायलट समर्थक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि पायलट को राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस पार्टी हर जगह भेजती है। उन्हें केवल एक एमएलए के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

राजस्थान में सियासी बदलाव और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बात करने पर चौधरी ने कहा कि सियासी बदलाव को लेकर निर्णय पार्टी लेती है और पार्टी आलाकमान ने जब पंजाब में चन्नी को सीएम बनाया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले रह गए और सब जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। इसी के साथ राजेंद्र चौधरी ने सचिन पायलट को राष्ट्रीय नेता बताते हुए यह तो नहीं कहा कि राजस्थान में सियासी बदलाव होगा, लेकिन उनके बयानों के मायने अलग ढंग से निकाले जा रहे हैं।

राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन और सियासी नियुक्तियों की बात पर उन्होंने कहा कि यह एक सिस्टम है। राजस्थान में जब मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ तो मंत्रियों के विभागों को बदला गया और मंत्रियों से किसी ने उसके बाद बात भी नहीं की।

- **पायलट समर्थक राजेन्द्र चौधरी बोले- ''जब पद चला जाता है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता''**

पद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी, तो गोविंद मोहन गुप्ता उनके सचिव थे और पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे रहती थी, लेकिन जब उनको वसुंधरा राजे ने हटाया तो वह एक अटैची के साथ अकेले ही एयरपोर्ट गए। यह सब बताता है कि पद के साथ हर कोई खड़ा होता है लेकिन जब पद चला जाता है तो कोई साथ खड़ा नहीं होता।

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा की अशोक गहलोत भी इस मामले में प्रियंका गांधी और अजय माकन से बात कर चुके हैं। जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। इसी के साथ सचिन पायलट को लेकर उन्होंने फिर कहा कि वे राष्ट्रीय नेता हैं और राजस्थान में जब 21 सीट कांग्रेस की आई थीं, तो सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपकर राजस्थान भेजा था और उन्होंने राजस्थान के दौरे कर फिर से सत्ता लाने के लिए मेहनत की।

लोहामंड़ी के विकास पर 19 करोड़ रु. खर्च करेगा जेडीए

जयपुर (कासं)। सीकर रोड पर करीब 135 बीघा की स्कीम लोहामंडी के विकास पर जेडीए प्रशासन 19 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि वर्तमान में लोहामण्डी शहर के मध्य चांदपोल क्षेत्र के पास स्थित है जो कि काफी भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। इससे वाहनों के आवागमन में असुविधा रहती है। लोहामण्डी को शहर से बाहर विकसित किये जाने से स्थानीय निवासियों व व्यवसायियों दोनों को लाभ होगा तथा यातायात भी सुगम होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की लोहामण्डी योजना माचेडा में विभिन्न विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

जेडीए की लोहामण्डी योजना माचेडा सीकर रोड और बैनाड रोड के मध्य स्थित है जो कि 135.39 हैक्टेयर में सृजित है। लोहामण्डी योजना में 1174 व्यवसायिक भूखण्ड एवं 962 रहवासीय भूखण्ड है।

योजना में भूखण्डों का डिमार्केशन, सुविधा क्षेत्र में कम ऊँचाई की परिधि वॉल, योजना की सम्पर्क सड़क का सुदृढीकरण, मुख्य सड़को का 3.90 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण व आन्तरिक सड़कों का 54.17 कि.मी. समतुल्य लम्बाई में जीएसबी द्वारा निर्माण कार्य पर राशि रुपये 19.81 रोड़ व्यय करते हुये कार्य सितम्बर, 2022 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना का 18.30 प्रतिशत रहवासीय, 28.15 व्यवसायिक रखा गया है, कुल क्षेत्रफल का 52.77 प्रतिशत सुविधा हेतु यथा रोड पार्क, आमजन के लिए रखा गया है साथ ही 47.03 प्रतिशत क्षेत्र में व्यवसाय के लिए रखा गया है।

किसानों के साथ सांसद किरोड़ी ने किया सिविल लाइंस कूच, पूर्ण कर्ज माफी की मांग उठाई

दंडवत प्रदर्शन कर किसानों ने विरोध जताया, पुलिस ने किरोड़ी को सीएमओ ले जाकर करवायी वार्ता

जयपुर (कासं)। सांसद किरोड़ी मीणा ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए याद दिलाया कि प्रदेश के किसानों का पूरा माफ होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने अभी किसानों की कृषि भूमि नीलामी आदेश को स्थगित किया है, जबकि पूर्ण कर्जा माफ करते हुए 15 लाख से अधिक किसानों की कृषि भूमि नीलामी के आदेश को निरस्त किया जाए।

डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने गुरूवार को बड़ी संख्या में पीड़ित किसानों के साथ सिविल लाइंस कूच करते हुए धरना दिया। सिविल लाइन फाटक पर दंडवत प्रदर्शन के बाद पुलिस किरोड़ी को सचिवालय ले गई। जहां सीएमओ में सरकार के साथ बातचीत में रामगढ़ पचवारा में पिछले दिनों की गई किसान आत्महत्या मामले में विधवा को 5 लाख के सरकारी सहायता की घोषणा करवाई।

डॉ. मीणा ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व चुनाव में राजस्थान के किसानों का 10 दिन में कृषि ऋण माफ करने का वादा किया था जिसे राहुल गांधी ने भी दौहराया था।

मुख्यमंत्री गहलोत ने भी राजस्थान के किसानों के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की थी। किंतु घोषणा के विपरीत किसानों की जमीन कुर्क किए जाने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर जारी है। मीणा ने बताया कि अकेले दौसा में 800-1000 किसानों, सवाई माधोपुर में 600-700 किसानों, करौली में करीबन 800 किसानों, अलवर जिले में करीबन 3000 किसानों, धौलपुर एवं भरतपुर में भी सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्क करने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं।

संपूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों ने सिविल लाइन्स फाटक पर दंडवत विरोध प्रदर्शन किया।

थानागाजी में करीबन 11 किसानों की जमीन नीलाम कर दी एवं रैण में आज करीबन 11 किसानों की जमीन नीलाम की जारी है। यह सब वो ऋण हैं जो सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक से लिए गए है।

उन्होंने कहा कि मोटे अनुमान के अनुसार करीबन 15 लाख किसानों का 10 हजार करोड रुपए के करीबन सहकारी बैंकों के कर्जे की तलवार किसानों पर लटकी हुई है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय के कजोड़ मीणा ने अपने खेत में ट्यूबवेल कराने के लिए वर्ष 2017 में 3 लाख 87 हजार रुपए का लोन लिया, जो इस समय ब्याज सहित करीब रुपए 7 लाख का हो गया।

बैंक के अधिकारी-कर्मचारी ने लोन जमा कराने का बार-बार तगादा किया, जिससे तंग आकर किसान कजोड़ ने 26 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली।

घटना के 2 माह बाद इस परिवार के घर फिर बैंक वाले जा धमके और लोन जमा कराने के लिए तंग करने लगे। तब 13 जनवरी को दर्जनों किसानों ने उपखंड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को एक ज्ञापन देकर मांग की, जिस ट्यूबवेल के लिए लोन लिया गया था वह फेल हो गई। इसलिए सेटेलमेंट कराकर लोन माफ कर जमा करा लिया जाए। इनकी जमीन को कुर्क नहीं किया जाए, करीबन 4 लाख 25 हजार रुपए का सेटलमेंट हो जाने तथा जमीन नीलाम नहीं किए जाने के आश्वासन के बाद परिवार घर लौटे।

- **रामगढ़ पचवारा में पिछले दिनों आत्महत्या करने वाले किसान की विधवा को 5 लाख रु. की सरकारी मदद की घोषणा करवाई**
- **कृषि भूमि नीलामी आदेश को स्थगित के बजाय निरस्त करे सरकार : किरोड़ीलाल**

इसके बावजूद 18 जनवरी को बैंक कर्मियों और राजस्व अधिकारियों ने मिलकर समूची जमीन करीबन 15 बीघा को जिस की डीएलसी रेट के हिसाब से कीमत 75 लाख बनती है तथा मार्केट रेट के हिसाब से 1 करोड रुपए है, उसको 46 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से नीलाम कर दिया। मात्र 7 लाख रुपये के लोन के लिए पूरी जमीन को नीलाम कर दिया और नीलामी के समय किसानों को भी नहीं बुलाया गया और ना ही अखबारों में विज्ञिप्त जारी की गई।

इस प्रकार अधिकारियों ने कानून को ताक में रखकर इस कजोड़ मीणा के परिवार को सड़क पर ला दिया। मेरे ट्वीट करने के बाद आनन-फानन में 19 जनवरी को उस नीलामी को रद्द कर दिया गया, इससे स्पष्ट है कि नीलामी अवैध थी। डॉक्टर मीणा ने कहा कि ऐसे और भी कई मामले आपके सामने लाऊंगा जहाँ सरकारी अधिकारियों ने किसानों की परिवार के परिवार उजाड़ दिए जो आत्महत्या करने पर मजबूर है।

सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड को भेजा जाएगा एक्शन प्लान

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि दिनेश कुमार ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक्शन प्लान बनाकर नाबार्ड को भेजा जाएगा ताकि किसानों को कृषि ऋण एवं अन्य ऋणों की सुविधा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सके। कुमार गुरूवार को शासन सचिवालय में एसएलडीबी एवं पीएलडीबी के लिए टर्न-अराउन्ड-प्लान को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड को जाने वाले एक्शन प्लान में ओटीएस स्कीम, अल्पकालीन पुनर्वित्त, विशेष तरलता सुविधा सहित अन्य बिंदुओं का समावेश कर तीन दिन के भीतर राज्य सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजें। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों के हितों के संरक्षण के लिए नई योजनाएं तैयार की जाएं। किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ओटीएस स्कीम एवं अन्य ब्याज अनुदान की योजनाओं पर जोर दिया जाए।

रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए लाई गई ऋण माफी योजना से करीब 29 हजार किसानों के लगभग 294 करोड़ के ऋण माफ हुए हैं।

साथ ही, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना से प्रतिवर्ष करीब 25 करोड़ रूपए का अनुदान किसानों को मिल रहा है। इस योजना से 5 प्रतिशत पर कृषि ऋण उपलब्ध हो रहा है। एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बैंकों के टर्न-अराउन्ड-प्लान के बारे में प्रजेन्टेशन दिया। बैठक में संयुक्त शासन सचिव सहकारिता नारायण सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार मार्केटिंग धनसिंह देवल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

जिला उपभोक्ता आयोग को हटाने के लिए सीएम को शिकायत भेजी

जयपुर। अभिभाषक परिषद, बूंदी ने जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी पर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग सहित अन्य को पत्र भेजा है।पत्र में कहा गया कि अध्यक्ष रविन्द्र कुमार माहेश्वरी की कार्य प्रणाली हाईकोर्ट की कोविड अधिसूचना के खिलाफ है। बूंदी में फैल रहे कोविड संक्रमण और हाईकोर्ट के ऑफ लाइन कार्य नहीं करने के निर्देश के बावजूद अध्यक्ष वकीलों को ऑफ लाइन काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

रीट पेपर लीक का मास्टमाइंड भजनलाल गुजरात से गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। एसओजी ने रीट पेपर लीक मामले में मास्टर माइंड भजनलाल विश्नोई को गुजरात से गिरफ्तार किया है। टीम गुरुवार को आरोपी को लेकर जयपुर पहुंची। बत्तीलाल समेत 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान भजनलाल का नाम सामने आया था, तभी से एसओजी उसे ढूंढ़ रही थी। भजनलाल से पूछताछ में रीट पेपर लीक से जुड़े कई खुलासे होने की भी संभावना है। पुलिस के मुताबिक भजनलाल ने रीट का पेपर 30 से 40 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को बेचा था। एसओजी की टीम पिछले 4 महीने से भजनलाल की तलाश में जुटी थी। इंस्पेक्टर मोहनलाल पोसवाल लगातार राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, गुजरात व उत्तरप्रदेश में दबिश दे रहे थे। इस बीच एसओजी को भजनाल के गुजरात में होने की सूचना मिली। टीम गुजरात पहुंची और भजनलाल को गिरफ्तार कर लिया। भजनलाल विश्नोई जालोर के रानोदर, चितलावना का रहने वाला है। गौरतलब है कि इसके बाद बत्तीलाल मीणा और पृथ्वीराज मीणा ने सवाईमाधोपुर और गंगापुरसिटी में कई अभ्यर्थियों को 10 से 12 लाख रुपये लेकर रीट का पेपर बेचा था।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि भजन लाल तीन साल पहले भी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था। इस दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इतना ही नहीं भजनलाल फर्जी डिग्रियों का भी मास्टर माइंड है।

निदेशक शपथ पत्र पेश कर बताए, क्यों नहीं हटाए अपात्र सफाई कर्मचारी?

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केकडी नगर पालिका में अदालती आदेश के बावजूद अपात्र सफाई कर्मचारियों को नहीं हटाने के मामले में नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय निकाय निदेशक और केकडी नगर पालिका के तत्कालीन व मौजूदा अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।

अदालत ने मामले में अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए स्थानीय निकाय निदेशक से पूछा है कि लापरवाही के लिए दोषी अधिशासी अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश रोहित कुमार की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया निंदनीय रहा है।

ऐसे में स्थानीय निकाय निदेशक मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालती आदेश की पालना नहीं होने के कारणों का पता लगाए और इस संबंध में शपथ पत्र पेश कर अदालत को अवगत कराए। अवमानना याचिका में कहा गया कि 19 सितंबर 2019 को हाईकोर्ट ने केकडी नगर पालिका को अपात्र व गलत दस्तावेज से चयनित सफाई कर्मियों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक उसकी पालना नहीं की गई है। ऐसे में अवमानना कर्ता दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए।

- **केकड़ी नगर पालिका में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई**

वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नियुक्ति में अनियमितता के कारण करीब 60 अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपात्र अभ्यर्थियों को हटा दिया गया, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को अदालती रोक के चलते हटाया नहीं जा सका।

जयपुर में करोना से दो और लोगों की मौत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर में गुरूवार को भी करोना संक्रमण से दो और लोगों की मौत हुई है। वहीं 2919 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा टोंक रोड और वैशाली नगर में 99-99 नए मरीज पाए गए हैं। हालाकि इस बीच साढ़े तीन हजार से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए हैं।

राजधानी जयपुर में गुरूवार को 102 इलाकों में नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सर्वाधिक वैशाली नगर और टोंक रोड इलाके में 99-99 नए संक्रमित सामने आए हैं। इसके अलावा गोविंदगढ़ में 98, सोडाला में 95, आमेर में 91, प्रतापनगर में 90, मालवीय नगर में 87, झोटवाड़ा में 85, दुर्गापुरा में 83, जगतपुरा में 82, मानसरोवर में 78, शास्त्री नगर में 77, एयरपोर्ट में 74, जवाहर नगर में 72, सांगानेर में 71, किरण पथ में 67, विद्याधर नगर में 62, पत्रकार कॉलोनी में 59, गोपालपुरा में 58 और अजमेर रोड इलाके में 50 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच 5 रोगी ऐसे है जिन्होंने जांच करवाते समय अपना नाम और पता सही नहीं लिखवाया।

- **टोंक रोड और वैशाली नगर में सर्वाधिक 99-99 नए संक्रमित मिले**

जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 3656 मरीज रिकवर भी हुए हैं। हालाकि अभी 20 हजार 90 एक्टिव केस मौजूद हैं।

राजधानी में गुरूवार को करोना से 2 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी अब तक जिले में 1995 लोगों की मौत हो चुकी है।

महिला अधिवक्ता की मौत की जांच अति. पुलिस अधीक्षक से कराओ

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा की अलवर में संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में अलवर एसपी को अपना अभ्यावेदन देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मामले की जांच दो माह में पूरी करें और एसपी मामले की मॉनिटरिंग करें। जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के महासचिव गजराज सिंह की आपराधिक याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष सोनल तनेजा का शव अलवर में संदिग्ध अवस्था में मिला था। घटना को लेकर गत 29 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले में मृतक के आत्महत्या करने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना संक्रमण के 681 और मामले बढ़े

राज्य में गुरूवार को 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं, इससे पहले बुधवार को 13 हजार 398 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में लगातार करोना संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है। गुरूवार को राज्य में 681 और मामले बढ़ने के साथ ही 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि राजधानी जयपुर में इनकी संख्या में कुछ कमी आई है। वहीं राज्य में 10 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। इस बीच प्रदेश में करोना से 13 और लोगों की मौत हो गई है।

प्रदेश में करोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते राज्य में गुरूवार को 14 हजार 79 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 13 हजार 398 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 391 मामले कम आने के साथ ही 2919 नए संक्रमित मिले हैं। हालाकि अलवर में थोड़ी और वृद्वि के बाद 1410 नए मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570, चित्तौड़गढ़ में 512, बीकानेर में 464, गंगानगर में 390, हनुमानगढ़ में 378, पाली में 364, सीकर में 362, बाड़मेर में 353, भीलवाड़ा में 293, डूंगरपुर में 292, सवाईमाधोपुर में 261, टोंक में 201, चूरू में 199, प्रतापगढ़ में 198, बांसवाड़ा में 187, जैसलमेर में 185, झालावाड़ में 176, नागौर में 173, राजसमंद में 170, झुंझुनूं में 161, दौसा में 157, सिरोही और बारां में 118-118, करौली में 114, बूंदी में 64, धौलपुर में 60 और जालौर में 12 नए संक्रमित सामने आए हैं।

प्रदेश में करोना से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। गुरूवार को भी राज्य में इससे 13 लोगों की जान चली गई। इनमें बीकानेर, जयपुर और कोटा में 2-2 तथा बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर और राजसमंद में 1-1 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9044 लोगों की मौत हो चुकी है।

इधर राहत की बात यह है कि राज्य में करोना से रिकवरी में लगातार सुधार हो रहा है। इसके चलते पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में 10 हजार 528 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9 लाख 96 हजार 940 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अभी भी 78 हजार 99 एक्टिव केस मौजूद है।

इनमें सबसे ज्यादा 20 हजार 90 मरीज जयपुर जिले में हैं। इसके अलावा अलवर में 7300, जोधपुर में 5384, उदयपुर में 4730, भरतपुर में 3588, कोटा में 3094, बीकानेर में 2907, अजमेर में 2795, पाली में 2750, बाड़मेर में 2544, चित्तौड़गढ़ में 2041, भीलवाड़ा में 1999, हनुमानगढ़ में 1891, सीकर 1666, सवाईमाधोपुर में 1616, गंगानगर में 1464, डूंगरपुर में 1061, प्रतापगढ़ में 1062 और चूरू में 1049 तथा शेष जिलों में इससे कम सक्रिय मरीज हैं।

- **हालाकि, इस बीच राजधानी जयपुर में थोड़ी कमी के बाद 2919 नए संक्रमित मिले हैं।**
- **राज्य में गुरूवार को करोना से 13 और संक्रमितों की मौत हो गई है।**
- **राहत की बात यह है कि पिछले चौबीस घंटों में साढ़े 10 हजार मरीज ठीक हुए हैं।**

लोहामंडी योजना की 35 बीघा भूमि की 22 वर्ष पहले 90बी हुई थी, लोग अभी तक पट्टे की खातिर तरस रहे

दूसरी तरफ 130 बीघा जमीन का 250 करोड़ रुपये मुआवजा उठा चुके काश्तकारों ने अब इस जमीन को खुद की बताकर संभागीय आयुक्त के पास अपील कर 90बी को चुनौती दी

जयपुर। सीकर रोड पर स्थित लोहामंडी योजना की जमीन का 250 करोड़ का मुआवजा उठाने के बाद अब काश्तकारों की निगाहें 90बी शुदा 35 बीघा जमीन पर खराब हो चुकी है। उन्होंने 22 साल पहले हुए 90बी के फैसले को अब संभागीय आयुक्त के यहां अपील दायर कर चुनौती दी है। जेडीए भी काश्तकारों को एक तरफा समर्थन करते हुए 90बी शुदा जमीन के भूखंडधारियों को मुआवजा और आवंटन पत्र नहीं दे रहा है।

सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सुरेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य ने यह कहते हुए संभागीय आयुक्त के यहां अपील की है कि 22 साल पहले जेडीए ने 16 अक्टूबर 1999 को उनकी 35 बीघा जमीन की 90 बी कर दी थी। इसमें 22 साल पूर्व के विलंब को क्षमा करते हुए इस जमीन का मालिकाना हक खुद का बताया है। साथ ही इस जेडीए के 90बी के फैसले को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की गई है।

- **ताज्जुब की बात यह है कि जेडीए प्रशासन भी काश्तकारों को एकतरफा समर्थन करते हुए 90बी शुदा जमीन के भूखंडधारियों को मुआवजा और आवंटन पत्र नहीं दे रहा**

इस जमीन को काश्तकारोंने इकरारनामा के जरिए मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दिया था। इसके आधार पर जेडीए ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था।

सूत्रों की मानें तो जेडीए ने यह जमीन 2002 से लेकर 2003 तक अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर अवाप्त कर ली थी। इसे मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति व अन्य ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इस जमीन पर 4 एस बी ब्लॉक के नाम से आवासीय योजना बस चुकी है। हाईकोर्ट ने अवाप्ति को सही ठहराते हुए समिति की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लोहामंडी की जमीन के मुआवजे के लिए लगे शिविर में जेडीए उपायुक्त अशोक कुमार योगी ने इनकी आपत्तियां खारिज कर दी थी। इस फैसले को काश्तकारों ने संभागीय आयुक्त के यहां चुनौती दी।

90बी शुदा जमीन के भूखंडधारियों का कहना है कि काश्तकारों को लगातार जेडीए प्रशासन से फेवर मिल रहा है। संभागीय आयुक्त के यहां 90बी के फैसले को चुनौती मिलने के बाद जेडीए के जोन उपायुक्त-6 अशोक कुमार योगी ने भूखंडधारियों को मुआवजा देने के सारे काम रोक दिए हैं। उनका कहना है कि काश्तकारों को मिल रहे फेवर के कारण अगर भूखंडधारियों के हित किसी भी प्रकार प्रभावित होते हैं तो इसके लिए जोन उपायुक्त ही जिम्मेदार होंगे।